



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बजट पर बहस एवं चर्चा का जवाब पेश किया।

‘देश में चार जातियां, युवा, महिला, किसान, और गरीब, हमारा बजट इन चारों के लिए है’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बजट को लेकर सदन में काफी कुछ कहा गया। यह बजट चहुँमुखी विकास करने वाला है। इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि विपक्ष के कुछ विधायकों ने भी खुले मन से तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि देश में चार जातियाँ हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। यह बजट इन चारों को आगे ले जाने वाला है।

मुख्यमंत्री शर्मा कहा कि राजस्थान की नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। कांग्रेस के लोग योजनाओं के नाम बदलने की चर्चा कर रहे थे। अनूपगढ़ रसाई का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। अरे भाई, एक परिवार के नाम कितनी योजनाओं के नाम करोगे? मां अनूपगढ़ के नाम से क्या दिक्कत थी। कांग्रेस में एक ही परिवार की भक्ति की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड़ा पर भी नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने अभी नेहरूजी का जिक्र किया, उन्होंने आगे भी स्वके नाम लिए। वो नाम नहीं लिए होते तो दामादजी का नाम कैसे आता। दामादजी का राजस्थान से क्या रिश्ता है, सब जानते हैं।

- मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया और बोले, वो कहते थे मांगते-मांगते थक जाओगे पर मैं देते-देते नहीं थकूंगा, पर सिर्फ थोथी घोषणाएँ कीं, एक भी घोषणा फलीभूत नहीं हुई।
- पेपर लीक पर मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कांग्रेस व डोटोसरा को घेरा और बोले, पेपरलीक इतने हुए, कितने करुं बयान, पास हुए “परिवारजन क्या-क्या करू बयान।”
- उन्होंने ई.आर.सी.पी. पर कांग्रेस की आलोचना की व कहा, ई.आर.सी.पी. हमारी सरकार लाई है। एम.ओ.यू. हमने किया, आपने क्या किया बता दीजिए।

मुख्यमंत्री ने कहा— इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शिनी था, महिलाओं की योजना का नाम कहां से दूढ़कर लाए। एक परिवार के प्रति ऐसा समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन आपातकाल के काले दिनों को भी याद कर लीजिए। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह संविधान की हत्या की गई थी।

संविधान हत्या दिवस का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और कुछ देर के लिए सदन में शोर-

लुटवाया अपना राज बचाने को। अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली।

पेपर लीक पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि अभी छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। वे बिल्कुल चिंता न करें, छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं बूज भूमि से आता हूँ, मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंसीवाले में अटूट आस्था है। आपको पता है, इनका जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, परंतु उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। सुदर्शन चक्र वाला जब आएगा तो बड़े-बड़े मगरमच्छों का भी इलाज होगा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा— श्रवण कुमार 44 साल से सदन में आ रहे हैं। मैं सीनियर हूँ, दर्द ज़ाहिर कर रहे थे। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। चवालिस सालों में एक भी कांग्रेस नेता ने पानी के लिए लेटर लिखा हो तो बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. लाई तो हमारी सरकार लाई। हमारी वसुंधरा राजे सरकार के समय बनी। आपने ई.आर.सी.पी. के लिए क्या किया, यह बता दीजिए। ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. हमने किया। कांग्रेस ने एम.ओ.यू. किया हो तो सदन में रख दीजिए। कांग्रेस वाले हमेशा भ्रम फैलाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कविता कहकर कांग्रेस और डोटोसरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “पेपर लीक इतने हुए, कितने करुं बखान, पास हुए परिवारजन, क्या-क्या करुं बयान। खूब करी मेहमान नवाजी अपनी सरकार बचाने को, जनता का पैसा

गुरुद्वारों पर अब भगवा झण्डा नहीं लहराया जायेगा

सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने यह फैसला जारी किया

नई दिल्ली, 29 जुलाई। खालसा पंथ की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा। सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने आदेश जारी किए हैं कि अब से इसका रंग बसंती होगा। यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अकाल तख्त साहिब में हुई पांच दिवसीय साहिबान की बैठक के बाद लिया है। इसी जैसी की ओर से एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कहा है कि केसरी निशान साहिब को लेकर संगत के बीच दुविधा थी। कुछ मामले अकाल तख्त साहिब के ध्यान में आए जिसके बाद इस पर चर्चा हुई। पांच दिवसीय साहिबानों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निशान साहिब का रंग बेशक भगवा है, लेकिन गलती से यह हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा रंग से मिला-जुला है। इस कारण कई बार संगत के लोग या अजनबी लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है, इस कारण

- अब पवित्र निशान साहिब पर फहराया जाने वाला झण्डा बसंती रंग का होगा।

कभी-कभी कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि हिंदू और सिख एक ही धर्म हैं। इस तरह के भ्रम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनका फैसला किसी धर्म या भगवा रंग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को किसी धर्म से जोड़कर विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला कोई नया नहीं है। अनुपालन परियोजना बिना किसी तय मानक के जारी किया गया है।

निशान साहिब सिखों के लिए पवित्र ध्वज होता है। यह हर गुरुद्वारे के बाहर फहराता रहता है। इसे वो अपनी धार्मिक रैलियों या धार्मिक-राजनीतिक रैलियों में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने वाहनों में सबसे ऊपर लगाकर भी चलते हैं। ये पवित्र त्रिकोणीय ध्वज कानून या रेशम के कपड़े का बना होता। इसके

जाएगा जो किसानों को उनका फसल का गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगा।

“मैं देश के किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो (एन.डी.ए.) ने नहीं किया, वो हम किसानों के लिए करेंगे। हम इस सदन में वैधानिक गारंटी वाला एम.एस.पी. (बिल) उनके लिए पारित करेंगे।”

गांधी ने आगे बोलते हुए “इंडिया गठबंधन” के दलों सहित वादा किया कि वे इस सदन में पारित करने के लिए विधिक गारंटीवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का (बिल) विधेयक लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना करने के लिए भी एक विधेयक इस सदन में पारित किया जाएगा, और इस कार्य को इंडिया गठबंधन पूरा करेगा।

उन्होंने सरकार को इस बात को लेकर

सिरे पर एक रेशम की लटकन होती है। इसे हर गुरुद्वारे के बाहर एक ऊंचे ध्वजडंड पर फहराया जाता है। सिख परंपरा के अनुसार निशान साहिब को फहरा रहे डंड में ध्वजकलश (ध्वजडंड का शिखर) के रूप में एक दोधारी खंडा (तलवार) होता है और डंडे को पूरी तरह कपड़े से लपेटा जाता है। झंडे के बीच में एक खंडा चिह्न होता है।

‘निर्देशों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परीक्षा की प्रक्रिया में शिथिलता नहीं दिला सकता। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पायल व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने आर.जे.एस. भती परीक्षा में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने ओ.एम.आर. शीट में उत्तर देते समय गोलों को सही तरीके से नहीं भरा है।

आलोचना की कि वह युवाओं को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चिन्ता की उपेक्षा कर रही है, विशेष रूप से बजट में पेपर लीक के मुद्दे पर। उन्होंने उल्लेख किया कि “पेपर लीक” युवाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है परंतु वित्त मंत्री ने अपने बजट में इसका उल्लेख नहीं किया।

गांधी ने केन्द्रीय बजट 2024 को “मध्यम वर्ग के लोगों की पीठ में छुरा धोकेने वाला बताया” और जोर देकर कहा कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य “बड़े व्यवसायियों को मजबूत करना है।”

आगे यह भी कहा कि “इस बजट में टैक्स आतंक के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी मार छोटे कारोबारियों पर बहुत पड़ी है। इसका एकमात्र उद्देश्य बड़े कारोबारियों के एकाधिकार

देवयानी से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों की सांभर थाना पुलिस ने पिटाई की



कांवड़ियों के साथ पुलिस मारपीट के विरोध में सोमवार को हिन्दू संगठनों ने सांभर थाने के आगे जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया।

- डीजे की धुन पर नाचते गाते लौट रहे कांवड़ियों को पुलिस ने रोका।
- विभिन्न हिंदू संगठनों ने सांभर थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
- मामले में एस.पी. ग्रामीण ने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।

कांवड़ियों के साथ पुलिस मारपीट के विरोध में सोमवार को हिन्दू संगठनों ने सांभर थाने के आगे जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया।

कहना था कि जब तक कांस्टेबल को सस्पेंड करने का ऑर्डर नहीं दिया जा जाएगा, वे यहां से हिलने वाले

‘हालांकि, भाजपा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मोदी सरकार की प्रशंसा के गीत गाते थकता नहीं है। राहुल ने संसद की कार्यवाही की कवरिंग करने वाले मीडिया का भी पक्ष लिया, यद्यपि, उनके अनुसार, इनमें से अधिकांश राहुल गांधी को ज्यादा जगह नहीं देते, बल्कि ज्यादातर तो उनकी उपेक्षा ही करते हैं।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें “कांच पिंजरे” से मुक्त कर दें। संसद की सिक्कोरिटी द्वारा मीडिया के सहायक गार्डों को सस्पेंड कर दिया है कि वे लोग मीडिया के लिये बनाये गये ग्लास कन्टेनर में ही रहें तथा नए भवन के प्रवेश द्वार पर सांसदों और

मन्त्रियों की बाइस्टस भी न लें, जिससे सांसद परेशान न हों। जब राहुल ने लोकसभा के पटल पर यह मुद्दा उठाया, तो मीडिया ने सांसदों आदि का बहिष्कार कर दिया तथा इस मुद्दे ने एक बड़ा रूप ले लिया।

4 जून से पहले वाले समय को बड़े पैमाने पर अलविदा कहते हुये, अब मुख्य धारा वाले चैनलों ने राहुल को दिखाना शुरू कर दिया है तथा उनके भाषण सोशल मीडिया पर हर समय दिखाई और सुनाई दे रहे हैं।

आगामी दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होंगे।

चौधरी ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल रात सांभर में कांवड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की घटना हुई है। उसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ।

पूर्व विधायक निर्मल कुमावत का कहना है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है तथा पुलिसकर्मियों को निर्लंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एडिशनल एस.पी. ब्रजमोहन मीणा का कहना है कि शिकायत पर चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है तथा अनुसंधान के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक सारिका खंडेलवाल का कहना है कि मामले की जांच कर सभी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बारामूला में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सोपोर कस्बे के शेर कालोनी में एक कबाड़ विक्रेता की दुकान के अंदर हुआ घटना के चक्कर कुछ लोग टुक से कबाड़ उतार रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि धमाके इतना जोरदार था कि दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की शिनाख्त नजीर अहमद नादरू (40), आजिम अशरफ मीर (20), आदिल राशिद दत्त (23) और मोहम्मद अजहर (25) के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य घायल भी हुआ है। वहीं, विस्फोट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इस वर्ष में ही राज्य के 45,485 करोड़ रूपए दिये हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में कहा कि विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तौर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनॉटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

कनॉटक सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर रही है। “इसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली चले गये।

वित्त मंत्री की आलोचना करते हुये, उन्होंने कहा कि केन्द्र की नीतियाँ उद्योगों को राज्य से बाहर खदेड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण, देश में एक.डी.आई. 31 प्रतिशत कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्वागत किया कि कनॉटक और महाराष्ट्र जैसे टैक्स की ज्यादा आय देने वाले राज्यों को आखिर बजट में क्या मिला। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, का कई विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तौर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनॉटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

झारखंड के मुख्यमंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एस.टी. पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का भी उल्लेख किया।

किन्तु उच्च न्यायालय ने कहा था, “यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता के आचरण को बहुत आगे की कोशिश की है, और इसका कारण रहा याचिकाकर्ता द्वारा ई.डी. के अफसरों के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. लेकिन इस केस का पूरा अवलोकन करने पर, ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि याचिकाकर्ता द्वारा उसी किस्म का अपराध कर रहा है।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा रिपोर्ट किये गये निष्कर्षों का परिणाम “प्रिवेन्शन ऑफ मनीलॉन्डरिंग” पर एक, 2002 के धारा की शर्त को सन्तुष्ट करता है तथा यह कथना प्रतीत होता है कि ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि याचिकाकर्ता

वनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने विन्दु को मजबूत देते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के साँतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कनॉटक के मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुये, वित्त मंत्री ने कहा कि यू.पी. सरकार के 10 वर्षों के दौरान, टैक्स के हस्तान्तरण के रूप में कनॉटक को प्रतिवर्ष 8,179 करोड़ रूपए मिला करते थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इस वर्ष में ही राज्य के 45,485 करोड़ रूपए दिये हैं।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में कहा कि विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रूख और तौर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कनॉटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

उस अपराध का दोषी नहीं है, जिसका आरोप उस पर लगाया गया है। ई.डी. ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके, राज्य की राजधानी के बाराेन क्षेत्र 8.86 एकड़ जमीन “गैर कानूनी रूप से” ले ली।

एजेंसी ने दावा किया था कि जाँच के दौरान, सोरेन ने मीडिया सलाहकार अधिकृत प्रसाद ने यह स्वीकार किया था कि एम.एम. नेता ने उन्हें निर्देश दिये थे कि सम्बन्धित भूखंड के स्वामित्व-विवरण को बदलने के लिये सरकारी रिकॉर्ड्स में हेर-फेर कर दिया जाये।

ई.डी. ने यह भी कहा कि जब जमीन के मूल स्वामी, राजकुमार पाहन ने उस समय शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, जब उसकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई।